



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937

No. 207]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SHRAVANA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

समापन अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

विषय : चीन जन. गण., कोरिया आरपी और चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की समाप्ति।

फा. सं. 15/18/2014-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण., कोरिया आर.पी. और चाइनिज ताईपय (जिन्हें एतदपश्चात "संबद्ध देश" कहा गया है) में उदभिवत अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पालियोल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 22.07.2009 की अपनी अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 15/19/2008 के तहत एक निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.08.2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 89/2009-सीमाशुल्क के तहत इस शुल्क का उदग्रहण किया गया था।

2. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाती है और उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, ऐसे साधन की समाप्ति होने से पहले युक्तियुक्त समयावधि के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

समीक्षा के लिए अनुरोध

3. और यतः, उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित याचिका यह आरोप लगाते हुए दायर किया था कि संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क प्रभावी होने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी हुई है और प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 89/2009-सीमाशुल्क के तहत उदग्रहित पाटनरोधी शुल्क और उसकी निरन्तरता की द्वितीय निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करे। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित था कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद पाटन की निरन्तरता बनी रही और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण क्षति की निरन्तरता बनी रही क्योंकि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा एवं उसका स्वरूप अपर्याप्त है। आवेदक ने पुनः यह तर्क दिया था कि संबद्ध देशों के विरुद्ध इस साधन की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरन्तरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आवेदक ने यह भी दावा किया था कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लेने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और भी अधिक बढ़ जाएगी, इसलिए इस शुल्क को अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ाना अपेक्षित है।

4. और यतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली कथित क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस बात पर विचार किया था कि लागू प्रतिपाटन शुल्क की सेनसेट समीक्षा की कार्रवाई शुरू करना संबद्ध देशों से आफ सेट पाटन की तरफ इस प्रकार के शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जांच पड़ताल जारी रखने के लिए समुचित होगा तथा इस प्रकार की जांच पड़ताल करने के लिए समुचित होगा कि क्या कि यदि संबद्ध देशों से शुल्क को हटा लिया जाता है अथवा अलग-अलग दरों में रखा जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को इससे क्षति होते रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत दिनांक 28 अगस्त, 2014 की जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या 15/18/2014 डीजीएडी के तहत की थी। मौजूदा शुल्क को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 42/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 30 अगस्त, 2015 तक, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं किया गया तो, बढ़ा दिया है।

जांच शुरुआत के पश्चात उत्तरवर्ती घटनाएं

5. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, घरेलू उद्योग ने अपने प्राधिकृत अधिवक्ता (विधिक प्रतिनिधि) के माध्यम से प्राधिकारी के समक्ष यह उल्लेख करते हुए एक पत्र भेजा है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में अब परिस्थितियों में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत से भीतरी अंतर आ चुका है; यह कि मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के अधिकतर आयात सिंगापुर और ईयू से हो रहे थे जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 07 अप्रैल, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क का पहले ही अधिरोपण किया है; यह कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु के अधिकतर आयात सिंगापुर और ईयू से ही हो रहे थे; यह कि उसी अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु का इन संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ था और इसलिए वे शुल्क का विस्तार करने के लिए निर्णायक समीक्षा के अपने आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

निष्कर्ष तथा सिफारिशें

6. घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी को यह सूचना प्रदान करते हुए उपर्युक्त पत्र के मद्देनजर कि वे संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में शुल्क में विस्तार करने के लिए निर्णायक समीक्षा हेतु दिए गए अपने आवेदन को वापस लेना चाहते हैं और इस मामले की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा में कोई और जांच करने की अब आवश्यकता नहीं है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पालियोल के आयातों पर प्राधिकारी द्वारा अपनी दिनांक 22 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/19/2008-डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जांच-परिणाम में यथा-संस्तुत और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2009 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 89/2009 के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 42/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 30 अगस्त, 2015 तक संवर्धित सीमा-शुल्क की निरन्तरता विच्छिन्न करने की सिफारिश की जाती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

Subject: Termination of Sunset Review anti dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from China PR, Korea RP and Chinese Taipei.

F. No. 15/18/2014-DGAD.— Whereas, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) vide its Final Findings Notification No. 15/19/2008 dated 22.07.2009, had recommended in a sunset review investigation, the imposition of anti-dumping duties on the imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as the subject goods or Product Under Consideration or FPS), originating in or exported from China PR, Korea RP and Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject countries) and the duties were levied by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 89/2009-Customs dated 31.08.2009.

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Request for Review

3. And whereas, in terms of the above provision, Manali Petrochemicals Limited filed a duly substantiated petition before the Authority alleging continued dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries in spite of duties in force and requested the Authority for initiation of second sunset review of the anti dumping duties levied by the Central Government on the subject goods originating in or exported from these countries vide Customs Notification No. 89/2009-Customs dated 31.08.2009 and continuation of the same. The request was based on the grounds that dumping had continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continued to suffer injury on account of dumping from the subject countries as the form and quantum of anti dumping duty in force had been insufficient. The applicant had further

argued that expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The applicant also claimed that revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry and, therefore, the duty was required to be continued for a further period of five years.

4. And, the Authority, on the basis of prime facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries and likely injury to the domestic industry, considered that initiation of sunset review proceedings for the antidumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied from the subject countries. The Authority, initiated the sunset review anti dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Initiation Notification No. 15/18/2014-DGAD dated 28th August, 2014. The existing duty was extended by the Central Government vide notification no. 42/2014-Customs (ADD) dated 25th September, 2014 up to 30th August, 2015, unless revoked earlier.

Subsequent Events after Initiation

5. M/s Manali Petrochemicals Ltd, the domestic industry, submitted letter to the Authority through their authorized legal representative stating that the situation with regard to the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has undergone significant changes since the initiation of the sunset review investigation; that the majority of the imports of the subject goods during the period of investigation in the present sunset review were coming from Singapore and EU against which the Central Government has already imposed anti dumping duty vide its Notification dated 7th April, 2015; that even during the post-POI period in the present investigation, the majority of the imports of the subject goods were still coming from Singapore and EU; that during the same period there were no imports of the subject goods from the subject countries and, therefore, they would like to withdraw their application of sunset review for extension of the duties.

Conclusions and Recommendations

6. In view of the said letter of the domestic industry informing the Authority that they would like to withdraw their application of sunset review for extension of the duties in respect of the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and after examining the matter, the Authority holds that there is no need for further investigation in the present sunset review and recommends discontinuation of anti dumping duty on the imports of Flexible Slabstock Polyol, originating in or exported from the subject countries as recommended by the Authority in the Final Findings issued vide Notification No. 15/19/2008-DGAD dated 22nd July, 2009 and imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 89/2009-Customs dated 31st August, 2009 and further extended by the Central Government up to 30th August, 2015 vide Notification No. 42/2014-Customs (ADD) dated 25th September, 2014.

J. K. DADOO, Designated Authority